कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड निम्नलिखित में निर्धारित किए गए हैं:

(ए) आर.पी.एफ अधिनियम 1957: -

<u>वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति:</u>

बल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है:

(i) कोई भी व्यक्ति, जो स्वेच्छा से चोट पहुंचाताहै, या स्वेच्छा से चोट पहुंचानेका प्रयास करता है, या गलत तरीके से बल सदस्य को कर्तब्य पालन से रोकता है या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, या हमला करता है, हमला करने की धमकी देता है, या आपराधिक बल प्रयोग करता है , या धमकी देता है या आपराधिक बल प्रयोग का प्रयास करता है, या बल के किसी अन्य सदस्य को ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के निष्पादन में, या उसे ऐसे सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से या कर्तव्य पालन से रोकता है या हटा देता है, या

(ii) कोई भी व्यक्ति जो रेलवे संपत्ति, यात्री परिसर, और यात्रीयो से संबंधित किसी ऐसे अपराध में शरीक रहा हो, रहने का उचित संदेह हो या जो ऐसी परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए प्रयत्न कर रहा हो, जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है कि वह ऐसा रेल सम्पत्ति, यात्री परिसर और यात्रियों से ही संबंधित हस्तक्षेप अपराध करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है या,

(iii) कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में रेलवे की सीमा के भीतर अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए प्रयत्न करता हु आपाया जाता है, जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है कि वह रेलवे संपत्ति ,यात्री परिसर और यात्रियों की चोरी या नुक़सान पहुँचानेकी अभिप्राय से ऐसा प्रयत्न कर रहा है या,

(iv) कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए ख़तरा उत्पन्न होता है या खतरा का अंदेशा हो जाता है जो कि रेलवे संपत्ति, यात्री परिसर और यंत्रियों से संबंधित किसी भी कार्य को करने में लगे है।

<u>वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति :</u>

(१) जब कभी किसी बल सदस्य, जो नायक के पद से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा १२ में निर्दिष्ट ऐसा कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और यह कि अपराधी को अपराध के साक्ष्य से बचने या छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह उसे हिरासत में ले सकता है और उसके जिस्म और सामान की तलाशी ले सकता है और, यदि वह उचित समझता है तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास अपराध करने का विश्वास करने का कारण है।

(२) उस संहिता के तहत तलाशी से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ का प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत तलाशी पर लागू होगा।

<u>गिरफ्तारी के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:</u>

इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी करने वाले बल का कोई भी सदस्य बिना किसी अनावश्यक देरी के, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंप देगा, या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को ले जाएगा या उसे निकटतम पुलिस स्टेशन भिजवाएगा ।

(बी) आर.पी.एफ नियम, 1987।

<u>बल की तैनाती पर प्रतिबंध:</u>

1. इस अध्याय में किसी भी बात के होते हु एभी, किसी भी सदस्य को यदि बल को कानून और व्यवस्था से संबंधित किसी भी कार्य को करने की अपेक्षा नही की जाएगी (सिवाय तब के जब अध्याय XVI के अधीन तैनात किया जाए) या उन समस्याओं पर ध्यान देने के लिए जो विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक प्रकृति की हैं, जिसमें यह माँग है की रेलवे

कर्मचारियों या रेलवे के उपभोक्ताओं द्वारा अनुशासन का मानक बनाए रखा जाना: परंतु रेलवे संपत्ति की बचाव और सुरक्षा के खिलाफ भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए बल को तैनात किया जा सकता है बशर्ते कि पुलिस या मजिस्ट्रेट के आने में देरी हो रही हो ।

2. नियम ४१.२(x) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना बल हड़ताल और तालाबंदी के दौरान रेलवे संपत्ति की बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सकता है और वफादार कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने और स्थानीय पुलिस की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपबंध कर सकेगा, अन्यथा।

3. लिखित में कारण दर्ज किए जाने के अलावा, बल के किसी भी सदस्य को रेलवे कॉलोनियों में तैनात नहीं किया जाएगा- (ए) आवारा मवेशियों, फेरीवालों, भिखारियों, असामाजिक तत्वों को पकड़ने और ऐसे ही किसी कार्य को करने के लिए,

(बी) रेलवे सहकारी समितियों द्वारा नियंत्रित वस्तुओं की बिक्री में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए;

(सी) यातायात को नियमित करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात ड्यूटी करने के लिए;

(डी) टोल टैक्स जमा करने के लिए; या

(ई) रेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों की रक्षा के लिए:

बशर्ते कि किसी भी रेलवे कॉलोनी में सब-स्टेशन, पंप हाउस आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बल को तैनात किया जा सकता है।

4. बल के किसी भी सदस्य को अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जे को हटाने या किरायेदारों या उप-किरायेदारों को या तो रेलवे स्टेशनों पर या रेलवे परिसर में बेदखल करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, जहां इस तरह के अतिक्रमण, सबलेटिंग के अनधिकृत कब्जे को वर्षों पहले रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकार किया गया है। या जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की समस्या होने की संभावना है।

5. बल के किसी भी सदस्य को किसी भी रेल कर्मचारी की बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या निलंबन के आदेश के लिए या किसी कर्मचारी के पूर्व कामों या चरित्र को सत्यापित करने के लिए तैनात नहीं किया जाएगा।

6. किसी भी ऐसे पोस्टर को हटाने के लिए बल के किसी भी सदस्य को नहीं बुलाया जाएगा जो रेल प्रशासन को आपत्तिजनक लगे, लेकिन यदि कोई अन्य रेल कर्मचारी ऐसे पोस्टरों को हटाने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो बल उसे सुरक्षा प्रदान करेगा।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया :

अधिनियम की धारा १४ के प्रयोजन के लिए धारा १२ के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या निकटतम पुलिस थाने को सौंपते समय , गिरफ्तारी का समय, तारीख और कारण बताते हुए एक संक्षिप्त नोट भी प्रस्तुत किया जाएगा और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा।

तलाशी :-

अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी व्यक्ति या उसके सामान की तलाशी के दौरान उचित रूप से चोरी या अवैध रूप से प्राप्त होने की संदेहास्पद रेलवे संपत्ति पाई जाती है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। या इस प्रकार बरामद संपत्ति के साथ पुलिस को भेजा जाएगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो।

(सी) रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966।

1. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति--कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या बल का सदस्य, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में शामिल है या जिसके खिलाफ उचित संदेह है की वह उसमें शरीक रहा है ।

2. गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ जाँच कैसे की जाएगी—

(1) जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए बल के एक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या धारा 7 के तहत उसे भेजा जाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप की जांच के लिए अग्रसर होगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए बल का अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उन्हीं प्रावधानों के अधीन होगा जो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी प्रयोग कर सकता है और वह दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ का ५)१ के अधीन है। जो संज्ञेय मामले की जांच करते समय की जाती है, परंतु;-

(ए) यदि बल के अधिकारी की राय है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है, तो वह या तो उसे मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए जमानत पर छोड़ देगा, या उसे हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा;

(बी) यदि बल के अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने पर, ज़मानत के साथ या बिना जमानत के छोड़ देगा की , जब ऐसा आवश्यक हो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष बुलाए जाने पर उपस्थित होगा, और मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा।

3. साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति-

(i) बल के एक अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझता है या तो सबूत देने के लिए या एक दस्तावेज पेश करने के लिए, या कोई अन्य चीज जो उसके क़ब्ज़े में हो या अधिकार में हो, समन करके तलब कर सकता है,

(ii) दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने के लिए एक समन चाहे किसी दस्तावेज या वस्तु के लिए या उस प्रकार के सभी दस्तावेजों और वस्तुओं को पेश करने के लिए हो सकता है जो उस व्यक्ति के क़ब्ज़े या अधिकार में हो।

(iii)इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है; और इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य होंगे, जिसके संबंध में उनकी जांच की जाती है या बयान देने और ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है: बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता १९८० की धारा 132 और 1 33 के तहत छूट लागू होगी।

(4)उपरोक्त के रूप में प्रत्येक ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के अंदर एक "न्यायिक कार्यवाही" मानी जाएगी।

4. तलाशी वारंट जारी करना-

(i) यदि बल के किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी स्थान का उपयोग रेलवे की संपत्ति को जमा करने या बेचने के लिए किया जाता है जिसे चुराया गया है या अवैध रूप से प्राप्त किया गया है, तो वह उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को तलाशी वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन करेगा जिसमें वह स्थान है।

(ii) जिस मजिस्ट्रेट को उप-धारा (१) के तहत आवेदन किया गया है, ऐसी जांच के बाद, जैसा वह आवश्यक समझता है, अपने वारंट द्वारा, बल के किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है-

(ए) ऐसी जगह सहायता के साथ प्रवेश करने के लिए जो आवश्यक हो,

(बी) वारंट में निर्दिष्ट तरीके से उसकी तलाशी लेना;

(सी) किसी भी रेलवे संपत्ति का कब्जा लेने के लिए जिसमें उसे चोरी या गैरकानूनी रूप से प्राप्त होने का उचित संदेह है; तथा

(डी) ऐसी रेलवे संपत्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना, या जब तक अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जाता है, तब तक मौके पर ही उसकी रक्षा करना अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा देना।

5. तलाशी और गिरफ्तारी कैसे की जाए— इस अधिनियम के तहत की गई सभी तलाशी और गिरफ्तारियां, तलाशी और गिरफ्तारी से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, (१८९८ का ५)१ के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।

<u>कुछ धाराओं के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तारी:-</u>

(१) यदि कोई व्यक्ति धारा १५० से १५२ में उल्लिखित कोई अपराध करता है, तो उसे बिना वारंट या अन्य लिखित प्राधिकार के किसी भी रेलवे कर्मचारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो, गिरफ्तार किया जा सकता है।

(२) यदि कोई व्यक्ति धारा १३७, १४१ से १४७, १५० से १५७, १६० से १६२, १६४, १६६, १६८ और १७२ से १७५ में वर्णित कोई अपराध करता है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है या अन्य लिखित प्राधिकार के किसी भी रेल सेवक द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। या पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो।

(३) रेल सेवक या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को उप-धारा (१) के तहत गिरफ्तारी के लिए उसकी सहायता के लिए बुला सकता है।

(४) इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

<u>व्यक्तियों के फरार होने की संभावना, आदि की गिरफ्तारी :-</u>

(१) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत धारा १७९ में वर्णित अपराध के अलावा कोई अपराध करता है, या धारा १३८ के तहत मांगे गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क या अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अपना नाम और पता देने में विफल रहता है या इनकार करता है या वहां यह मानने का कारण है कि उसके द्वारा दिया गया नाम और पता काल्पनिक है या वह फरार हो जाएगा, इस संबंध में अधिकृत कोई भी रेल कर्मचारी या हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो कोई भी पुलिस अधिकारी उसे वारंट या लिखित अधिकार के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

(२) रेल सेवक या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को उप-धारा (१) के तहत गिरफ्तारी के लिए उसकी सहायता के लिए बुला सकता है।

(३) इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जब तक कि वह जमानत देने पर पहले रिहा नहीं हो जाता। या यदि उसका सही नाम और पता उस पर अपराध के लिए मुकदमा चलाने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए जमानत के बिना एक बांड निष्पादित करने पर पता लगाया जाता है।

(४) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के अध्याय XXIII के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, इस धारा के तहत जमानत देने और बांड के निष्पादन पर लागू होंगे।

<u>अपराध के घटित होने का पता लगाने के लिए अधिकारी द्वारा जांच :-</u>

किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए, अधिकृत अधिकारी 179 की उप-धारा (2) में उल्लिखित अपराध की जांच कर सकता है और सक्षम अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है यदि अपराध किया गया पाया जाता है .

<u>जाँच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियाँ:-</u>

जांच करते समय प्राधिकृत अधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि:-

(१) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को सुनिश्चहित करना और उसका बयान रिकॉर्ड करना ।

(२) किसी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता।

(३) किसी कार्यालय अधिकारी या व्यक्ति से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना।

(४) किसी भी परिसर में प्रवेश करें या व्यक्ति और उसकी तलाशी लें और किसी संपत्ति को जब्त करें या दस्तावेज जो जांच की विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक हो जप्त कर सकता है।

<u>गिरफ्तार व्यक्ति का निस्तारण :-</u>

धारा 179 की उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, यदि गिरफ्तारी अधिकृत अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, तो बिना देरी के ऐसे अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

<u>गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ पूछताछ कैसे की जाए:-</u>

(१) जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(२) इस प्रयोजन के लिए, अधिकृत अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो एक संज्ञेय अपराध की जांच करते समय एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में प्रावधानों और सीआरपीसी के प्रावधानों के अधीन होगा।

यह भी :----

(ए) यदि अधिकृत अधिकारी की राय है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत है या संदेह का उचित आधार है तो या तो उसे मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत के लिए स्वीकार करेगा या उसे ऐसे मजिस्ट्रेट की हिरासत में भेज देगा।

(बी) यदि अधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो वह आरोपी व्यक्ति को जमानत के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, जैसा कि अधिकृत अधिकारी उपस्थित होने के लिए निर्देश दे सकता है यदि और जब अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा आवश्यक हो।

<u>तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कैसे की जाए:-</u>

इस अधिनियम के तहत की गई सभी तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

<u>पूछताछ के संबंध में कुछ अपराधों के लिए सजा:-</u>

जो कोई भी जानबूझकर जांच की कार्यवाही में किसी भी तरह का अपमान या बाधा उत्पन्न करता है या जानबूझकर जांच अधिकारी के सामने झूठा बयान देता है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या 1000 / - या दोनों का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(e) सुरक्षा निदेशालय, रेलवे बोर्ड से समय-समय पर जारी स्थायी आदेश।

(फ) रेलवे बोर्ड का समय-समय पर जारी परिपत्र।

-0O0-